an>

Title: Regarding Parameters for development in Naxal affected areas in the country.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अखबार में जो छपा है, स्किल डैवलपमेंट मंत्रालय की न्यूज़ छपी है, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उस तरफ आकृÂट करना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार ने जो इस देश का कबाड़ा किया, वह अभी तक कंटीन्युअस प्रोसैस चल रहा है। हमारी सरकार आने के बाद भी हमने उन चीजों से सीख नहीं ली है और यू.पी.ए. का जो मतलब था कि show me the face, we will show you the rule. आप मुझे चेहरा दिखाइये और मैं आपको कानून बताऊंगा। इस देश में जैसे बी.पी.एल. के लिए लकड़वाला कमेटी थी, लकड़वाला कमेटी के बाद तेंदुलकर कमेटी बन गई, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी बन गई, आपको पता है, रंगराजन कमेटी बन गई, हाशिम कमेटी बन गई और यह तय नहीं हो पाया, क्योंकि, प्लानिंग कमीशन कोई अलग बी.पी.एल. का क्राइटीरिया तय करता था, रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय कोई अलग क्राइटीरिया तय करता था और केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री कोई अलग क्राइटीरिया तय करते थे, इस कारण से गरीब कौन है, गरीबी रेखा के नीचे कौन है, यह तय नहीं हो पाया।

उसी तरह से प्लानिंग कमीशन का नक्सलवादी जिलों के बारे में अलग क्राइटीरिया था, वे एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स थे, आई.आई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स थे, रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय अलग सोचता था और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, वह अलग सोचता था। इस कारण से जो क्राइटीरिया बना, प्लानिंग कमीशन ने कहा कि 34 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जो रूरल डैवलपमेंट मंत्रालय है, उसने तय किया कि 71 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और जो इस देश का गृह मंत्रालय है, उसने हमेशा कहा, एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर कि 106 से लेकर 111 जिले नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब एफ.एम. ऑक्शन होने लगा और आई.एण्ड बी. मिनिस्ट्री और होम मंत्रालय में जब लड़ाई शुरू हो गई तो फाइनली कैबिनेट ने यह तय किया कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय है, वही तय करेगा कि नक्सलवादी कौन है और आतंकवादी कौन है और वहां किस तरह का विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा विÂाय नहीं है, विÂाय यह है कि जो भी नक्सलवाद के जिले होंगे, उनमें स्वास्थ्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगी, उनका एजुकेशन का लेविल क्या होगा, उनमें रोजगार की समस्या कैसे होगी, उद्योग-धन्धा कैसे लगेगा, यह इम्पोर्टेंट है। उसमें रोड कैसे बनेगी, रूरल रोड कैसे बनेंगी, इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है कि होम मंत्रालय एस.आर.ई. डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर जो नक्सलवादी जिले घोÂिात किये हुए हैं, उसी को आप एक क्राइटीरिया मानिये और जिलों का विकास करिये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri Sunil Kumar Singh, Bhairon Prasad Mishra, are allowed to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): निशिकान्त जी ने जो एस.आर.ई. जिले घोÂिात हुए हैं, जिनमें स्किल डैवलपमेंट के बारे में जिस समाचार का ये रैफरेंस कर रहे हैं, उसका मैं संज्ञान लूंगा। यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि लैफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट्स इफैक्टिड डिस्ट्रिक्ट्स में गृह मंत्रालय नोडल है, क्योंकि, कई मंत्रालय इस काम को कर रहे हैं, कई अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कई काम अभी होने हैं। लेकिन जिस प्रकार से निशिकान्त जी ने इस पूरे विÂाय को रखा है और पूरे अध्ययन के साथ रखा है, मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्धित और गृह मंत्रालय के माध्यम से एल.डब्लू.ई. डिस्ट्रिक्ट्स में किस प्रकार के स्किल डैवलपमेंट का काम हो सकेगा, एक समन्वय स्थापित करके गृह मंत्रालय के साथ इस काम को करूंगा और निश्चित रूप से माननीय संसद को भी इस पूरे विÂाय की जानकारी दूंगा।